BAKHT): (a) Works relating to the main building and other connected items concerning the Parliament House Annexe were sanctioned between 1968 and 1975, through different estimates totalling upto Rs. 2,20,52,901. The total expenditure on the works is, however, expected to be Rs. 3,75,00,000.

The main reasons for increase are:—

(i) increase in the material and labour cost;

(ii) additional items of work and additional amenities; and

(iii) change in specifications during the execution of work.

(b) The amount of original estimate was Rs. 32,87,831 (including Departmental Charges). The expenditure upto March 1977 was Rs. 25 95,138 (including Departmental Charges). The variation is not large.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1260/77].

(d) No, Sir.

(e) Grounds have not come to light to warrant enquiry.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेघर परिवार

2519. **श्री छविराम अर्गल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1977 को देश के प्रत्येक राज्य में अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के बेघर परिवारों की संख्या क्रमश: कितनी थी ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें उपर्युक्त परिवारों के लिये मकानों की कमी के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के कितने परिवारों के लिये मकानों का निर्माण किया गया है ;

(घ) स्लाटों का आवंटन तथा स्थल पर कब्जा किये जाने वाले परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में बेघर लोगों को बसाने के लिए क्या विभिन्न उपाय किये गये है और इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ङ) : अनसूचित जातियों व अनसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आवास की कमी का कोई विशिष्ट अनुमान तैयार किया गया है ।

आवास राज्य का विषय है और राज्यों को सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं (आवास योजनाओं सहित) के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित अनुदानों' तथा 'समेकित ऋणों' के रूप में दी जा रही है ।

इसके अलावा, राज्य क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के कार्यक्रम के अधीन अनसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने के लिए राज सहायता देने की एक योजना है ।

जिन परिवारों को आवास स्थल दिए गए है उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं, उनकी संख्या
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
2.	असम	7,834
3.	बिहार	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
4.	गुजरात	1,51,921
5.	हरियाणा	1,36,130
6.	हिमाचल प्रदेश	2,556
7.	जम्मू व कश्मीर	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
8.	कर्नाटक	2,59,727
9.	केरल	28,760
10.	मध्य प्रदेश	4,54,862
11.	महाराष्ट्र	1,63,800
12.	उड़ीसा	31,278
13.	पंजाब	*.
14.	राजस्थान	6,11,820
15.	तमिल नाडु	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
16.	त्रिपुरा	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
17.	उत्तर प्रदेश	9,93,816
18.	पश्चिम बंगाल	1,77,787
1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं
2.	चण्डीगढ़	13
3.	दादर तथा नागर हवेली	715
4.	दिल्ली	5,934
5.	गोआ, दमण तथा दीव	318
6.	पांडिचेरी	1,138

*इस राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आबंटित आवास-स्थलों के पृथक आंकड़े नहीं रख रहे हैं क्योंकि इस योजना में आवास स्थलों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में कोई अन्तर नहीं है । तथापि, राज्य सरकार का अनुमान है कि जिन परिवारों को आवास-स्थल दिये गए है उनमें से लगभग 75 प्र० श० परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं । इस आधार पर पंजाब में अनुसूचित जाति/जन जाति के लगभग 2.25 लाख परिवारों को आवास-स्थल दिए गए हैं ।

आलू का उत्पादन

2520. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : रोग मुक्त आलू के बीजों की सप्लाई, उत्पादन बढ़ाने का एक अत्यंत